संसद में एक विधेयक पारित किया गया था तथा केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई जिसमें विभिन्न उत्तर पूर्वी राज्यों में छः महाविद्यालय हैं।

आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विभिन्न शाखाओं में 15 नयी योजनाओं जैसे एक संस्थान, 7 राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्र, 2 अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान प्रायोजना, 1 नेटवर्क तथा 4 अन्य योजनाओं (शिक्षक योजनाएं) का प्रस्ताव रखा गया है।

जवाहर लाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय को आवंटित धनराशि

4426. **श्री शिव प्रसाद चनपुरिया** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने जवाहर लाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय को चारा उत्पादन हेतु कितनी धनराशि आवंटित की है ;

(ख) पिछले तीन वर्षों में जवाहर लाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय द्वारा कितने मूल्य के चारे का उत्पादन किया गया;

(ग) उपर्युक्त विश्वविद्यालय द्वारा उत्पादित चारे का उपयोग कौन करता है ; और

(घ) क्या चारा उत्पादन इकाई में बीज उत्पादन की भी अनुमति दी गई है और क्या ये बीज किसानों को उपलब्ध कराये जाते हैं ?

गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री और कृषि मंत्रालय में राज्यमंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री एस. कृष्ण कुमार): (क) से (घ) जवाहर लाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय से सूचनाएं एकत्रित की जा रही है।

सूखे से प्रभावित लोगों को सहायता देना बन्द किया जाना

4427. **श्री कामेश्वर पासवान** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नलकूप/बांस बोरिंग, सिंचाई कूप और "डग वैल" के निर्माता तथा पम्प सेटों के वितरण जैसे किसानोपयोगी कार्यक्रम के लिए सरकार द्वारा दी जाने वाली 50 प्रतिशत की वित्तीय सहायता इस वर्ष बन्द कर दी गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और यदि नहीं, तो इस वर्ष दी गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या यह भी सच है कि उपर्युक्त सहायता बंद कर देने से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के किसान, सीमान्त किसान और छोटे किसान प्रभावित होंगे जिन्हें क्रमशः शत प्रतिशत, दस प्रतिशत और पचहत्तर प्रतिशत राज-सहायता स्वीकार्य है ?

कृषि मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) और (ख) उथले नलकूप/खुदे हुए कुओं के निर्माण के लिये छोटे और सीमांत किसानों को सहायता देने की केन्द्रीय प्रायोजित योजना, राष्ट्रीय विकास परिषद् के निर्णय के अनुसार पहली अप्रैल, 1992 से राज्यों को हस्तांतरित कर दी गई थी तथा धन भी उसी वर्ष संबंधित राज्यों को हस्तांतरित कर दिया गया था।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता।

जवाहर लाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर

4428. **श्री शिव प्रसाद चनपुरिया** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय की

अपनी स्वयं की उत्पादन इकाइयों के उत्पादन से कितनी बिक्री, कितनी आय रही है ; और

(ख) क्या यह सच है कि जवाहर लाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर विभिन्न अनुदान प्राप्त करने के बावजूद घाटे में चल रहा है; और इसकी उत्पादन इकाइयों को निजी हाथों में सौंपने और कर्मचारियों की छंटनी करने की कोई योजना विचाराधीन है?

गैर पारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री और कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) और (ख) जवाहर लाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर से सूचनाएं एकत्रित की जा रही हैं।

Subsidy on phosphatic fertilizer

4429. SHRI H. HANUMANTHAPPA: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether a decision was taken by Government for higher subsidy on phosphetic fertilizer recently;

(b) if so, the quantum and amount of subsidy announced on the fertilizers;

(c) whether the subsidy on DAP announced by Government is higher than last year; and

(d) details of the subsidy announced by Government on various types of fertilizers keeping in view the requirements of the farmers this year?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI ARVIND NETAM): (a) to (d) The scheme for sale of decontroiled fertilizers with concession to the farmers initiated in Rabi 1992-93 is being continued in 1993-94 with a provision of Rs. 756 crores. The concession will be available for the grades of fertilizers indicated below:

Product	Amount of concession (Rs. in Crores)	Rate of concession (Rs. per tonne)
Indigenous DAP	309	1000/-
MOP	120	1000/-
SSP	110	340/-
Indigenous Complexes	217	435—999/-

While a concession of Rs. 200 crores was provided for DAP (indigenous and imported) during 1992-93, this year it has been restricted to the indigenous product only with no change in the rate of concession.

Subsidy on Fertilizers

4430. SHRI SHIVAJIRAO GIRIDHAR PATIL: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government are providing subsidy on fertilizer during 1993-94;

(b) if so, what is the rate of subsidy per ton for indigenously manufactured diammonium phosphate (DAP), single super phosphate (SSP) and Muriate of Potash; and

(c) what would be the total financial impact of it on the budget and how it is going to be coped with?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI ARVIND NETAM): (a) to (c) The scheme for sale of decontrolled fertilizers with concession to the farmers initiated in Rabi 1992-93 is being continued in 1993-94. The concession will be available for the grades of fertilizers indicated below: